शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भी परमाणु उर्जा ख़तरनाक

जापान में आये भूकंप और सुनामी से वहां जो भयानक स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ख़तरनाक बात तो यह हुई है कि वहां के कुछ परमाणु रियेक्टर क्षतिग्रस्त हो गये हैं और परमाणु विकिरण का बड़ी ही तेज़ी से फैलाव हो रहा है। इस विकिरण को रोक पाने में जापान और दुनिया भर के वैज्ञानिक अक्षम हैं। इस विकिरण से जापान की जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसमें दो राय नहीं है। सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है और टोकियो की जनता को घरों में बंद रहने को कहा है, पर लोग़ घरों में आख़िर कितने दिनों तक बंद रह सकते हैं। परमाणु विकिरण का फैलाव रूस तक हो गया है और रूसी वैज्ञानिक इससे बचाव के उपाय ढूंढ रहे हैं।

परमाणु विकिरण का मतलब है मानो हवा में जानलेवा ज़हर का घुल जाना। इसके संपर्क में आने पर व्यक्ति की मौत सुनिश्चित है। अगर विकिरण की मात्रा कम है तो व्यक्ति तो तुरंत नहीं मरेगा, पर तरह-तरह की बीमारियों विशेषकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का शिकार हो कर तिल-तिल कर मरने पर मजबूर हो जायेगा। यही नहीं, आने वाली पीढ़ियों पर भी परमाणु विकिरण का दुष्प्रभाव पड़ेगा और वे शारीरिक व मानसिक रूप से विक्लांग पैदा होंगी।

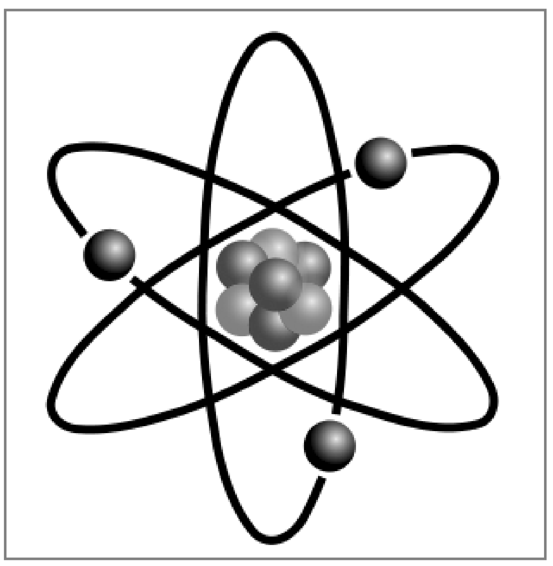

जापान परमाणु विस्फोट के ख़तरे को झेल चुका है। द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत में अमेरिका ने जापान के दो शहरों - हिरोशिमा और नागाशाकी पर परमाणु बम गिराये थे जिसकी चपेट में आकर वहां के लाखों लोग़ों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस विस्फोट के छः से भी ज़्यादा दशक गुजर जाने के बावजूद वहां अभी भी उस विस्फोट से हुए परमाणु विकिरण का प्रभाव कायम है और प्रभावित लोग़ों के बच्चे विक्लांग पैदा होते हैं। जापान के दो शहरों पर परमाणु विस्फोट कर अमेरिका ने दुनिया को अपनी मारक शक्ति से परिचित कराया था और मानवता को शर्मसार कर दिया था। आज जापान अमेरिकी गुट में शामिल है, पर इस संकट की घड़ी में अमेरिका उसकी मद के लिए सामने नहीं आ रहा है। जापान ने घोषित रूप से परमाणु बम नहीं बनाये हैं, पर अपनी उर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने बड़े पैमाने पर परमाणु रियेक्टर लगाये हैं। पर परमाणु रियेक्टरों से हुआ विकिरण भी परमाणु बम विस्फोट से कम ख़तरनाक नहीं होता। यह बात अब जापान के लोग़ों को समझ में आ रही है। इसके साथ ही दुनिया के अन्य देशों में भी यह विचार शुरू हो गया है कि परमाणु उर्जा कितनी सुरक्षित है। जर्मनी जैसा विकसित देश भी जापानी परमाणु संयंत्रों में विस्फोट के बाद इस मुद्दे पर सोचने के लिए बाध्य हो गया है। जर्मनी के लोग़ों ने परमाणु संयंत्रों की उम्र बढ़ाये जाने और इन संयंत्रों के भविष्य को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किया है। इस मुद्दे को लेकर जर्मनीवासियों ने मानव श्रृंखला का निर्माण किया और पीला झंडा लहराया जिस पर लिखा था - 'परमाणु उर्जा नहीं चाहिए।' जर्मनी की पुलिस के अनुसार इन प्रदर्शनों में 60 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए जर्मनी की चांसलर एजेंला मर्केल ने देश के परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा संबंधी मानकों की जांच करने का आदेश दिया है। इसके अलावा अन्य विकसित देश भी परमाणु सुरक्षा के मुद्दे पर विशेष रूप से विचार कर रहे हैं। रूस जैसा देश जो परमाणु बम बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर था, चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना को नहीं भूल सकता जिसमें हज़ारों लोग़ों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और विकिरण के प्रभाव क्षेत्र में आई ज़मीन भी बंजर हो गई थी।

आज दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु बम अमेरिका के पास हैं। अमेरिका इन्हीं बमों से दुनिया के कमज़ोर और ग़रीब देशों को धमकाता है, परिणामस्वरूप अमेरिकी दादागिरी के कहर से बचने के लिए विकासशील देशों जैसे भारत और पाकिस्तान ने भी ब्रह्मास्त्र से भी सहांरक परमाणु बम बना लिये और उनका विस्फोट कर के दुनिया को दिखा दिया कि वे भी किसी से कम नहीं है। आज दुनिया के देशों में परमाणु बम बनाने की होड़ लगी हुई है। ग़रीब से ग़रीब देश भी चाहता है कि वह परमाणु शक्ति संपन्न हो, भले ही जनता भूख से मरने पर विवश हो। दरअसल, इसके पीछे भय का मनोविज्ञान काम करता है। आज उत्तर कोरिया ने भी अमेरिका के लाख विरोध और प्रतिबंधों के बावजूद परमाणु बम बना लिया। ईरान भी इसी रास्ते पर चल रहा है जबकि अमेरिका लगातार इसका विरोध कर रहा है अपनी कठपुतली अंतरराष्ट्रीय परमाणु उर्जा आयोग के माध्यम से यह प्रयास कर रहा है कि ईरान परमाणु उर्जा शक्ति संपन्न न हो। पर ईरान अपने मिशन को पूरा करने के लिए अड़ा हुआ है, परिणामतः उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने उसे शैतान राष्ट्रों की धुरी में शामिल कर दिया है।

बहरहाल, जापान की दुर्दशा से यह साबित हो गया है कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भी परमाणु उर्जा का प्रयोग अत्यंत ही ख़तरनाक है। पहले यह तब साबित हुआ था जब सोवियत संघ के चेर्नोबिल में परमाणु दुर्घटना हुई थी। पर उस दुर्घटना से भी दुनिया भर के पूंजीवादी-साम्राज्यपरस्त शासकों ने कोई सीख नहीं ली।

पूंजीपतियों-साम्राज्यवादियों को बेहिसाब मुनाफ़ा चाहिए। इसके लिए अधिक से अधिक उत्पादन करना उनका लक्ष्य है और इसके लिए उर्जा की जरूरत पड़ती है। प्राकृतिक संसाधनों की उर्जा सीमित है और इसका अंधाधुंध दोहन करने पर यह उर्जा एक दिन समाप्त हो जायेगी। फ़िर मानव का अस्तित्व भी नष्ट हो सकता है। बावजूद इसके अपनी लालच में पूंजीपतियों ने प्राकृतिक उर्जा के संसाधनों का बेहिसाब दोहन किया और इससे प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। बड़े पैमाने पर प्रदूषण, वातावरण में विषैली ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन इसी का परिणाम है। इससे ऋतुचक्र में भी बदलाव आ रहा है और पूरी पृथ्वी का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पर लालची पूंजीपतियों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। उन्हें अपने मुनाफ़े के निरंतर बढ़ते जाने से मतलब है।

लेकिन अब यह साबित हो गया है कि परमाणु उर्जा का प्रयोग ख़तरनाक है। यह एक अजीब बात है कि दुनिया के अधिकांश देश जहां इस बात को लेकर चिंतित हैं, भारतीय शासक वर्ग को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। इस देश के शासकों ने वामपंथी दलों के विरोध की जरा भी परवाह नहीं करते हुए 2008 में अमेरिका से परमाणु समझौता किया जो हर दृष्टि से राष्ट्रहित के विरुद्ध है। पर शासक अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आये। अब इस समझौते की आड़ में अमेरिका और यूरोप के अन्य विकसित देश अपने यहां का कबाड़ा पड़ा रियेक्टर भारत को भारी कीमतों पर बेचेंगे और अगर उनसे कोई दुर्घटना भी होती है तो कतई उसकी ज़िम्मेवारी नहीं लेंगे।

सरकार महाराष्ट्र के जैतापुर में परमाणु परियोजना लगाने जा रही है। लोग़ों ने इस परियोजना का भारी विरोध कर रहे हैं। लोग़ों के विरोध को देखते हुए पर्यावरण एवं वनमंत्री जयराम रमेश ने इस परियोजना को मंजूरी देने से इंकार कर दिया था। पर साम्राज्यवादी दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा और इस परियोजना को हरी झंडी दे दी गई। अब इस परियोजना पर काम चल रहा है और यहां फ्रांस की एरेवा कंपनी अपना परमाणु रियेक्टर लगाने जा रही है। पर यह परियोजना पर्यावरण और सुरक्षा की दृष्टि से ख़तरनाक है। यही कारण है कि जापान में हुई परमाणु दुर्घटना के बाद वामपंथी दलों ने सरकार से यह मांग की है कि वह तुरंत जैतापुर परियोजना को बंद कर दे। यही नहीं, देश की आणविक उर्जा की शीर्षस्थ नियामक संस्था एईआरबी के पूर्व चेयरमैन डॉ.ए.गोपालकृष्णन ने जैतापुर परियोजना पर उठ रही चिंताओं के संदर्भ में कहा है कि 'मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि विदेश से रियेक्टर आयात करने संबंधी तमाम कामों को वह रोक दे और देश द्वारा खुद विकसित प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रियेक्टर (पीएचडब्लूआर) को ही बनाने और लगाने की प्रक्रिया को सोच-समझ कर आगे बढ़ाये।

जैतापुर में जिस तरह फ्रांसीसी कंपनी एरेवा का पूरी तरह से परीक्षण रहित ईपीआर रियेक्टर लगाया जा रहा है, वह सही नहीं है। मौजूदा ख़तरों को देखते हुए सरकार को जैतापुर परियोजना में एरेवा के रियेक्टर की खरीद को स्थगित करना चाहिए, क्योंकि परमाणु संयंत्रों में जोखिम लेने का समय नहीं है।' उन्होंने यह भी कहा है कि 'भारत का मौजूदा परमाणु सुरक्षा प्रबंधन अभी सरकारी तंत्र की वजह से गहरे संकट में है। अगर भारत को ऐसे ख़तरों से निपटने के लिए अपने को तैयार करना है तो एईआरबी (एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड) को सरकारी दबदबे यानी आणविक उर्जा विभाग (डीएई) से मुक्त करना होगा और उसमें ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों को शामिल करना होगा।' पर सरकार का हर विभाग पूरी तरह से नौकरशाही पर आधारित है।

क्या सरकार ख्याति प्राप्त परमाणु वैज्ञानिक डॉ.ए.गोपालकृष्णन की राय पर ध्यान देगी या अपने कानों में अंगुली डाले रहेगी? सरकार को इस देश की जनता के हित के लिए जैतापुर परमाणु परियोजना को तत्काल बंद करना चाहिए और विकसित पश्चिमी देशों से सड़े-गले रियेक्टरों का जो सौदा उसने किया है, उसे भी तत्काल रद्द कर देना चाहिए। पर कमीशनखोर नेता क्या ऐसा करेंगे? लगता तो नहीं है। उन्हें लोग़ों की जान की परवाह कतई नहीं है। उन्हें कमीशन के रूप में मिलने वाले उन डालरों की परवाह है जिन्हें वे विदेशी बैंकों में जमा करायेंगे। सरकार को जैतापुर परियोजना तुरंत बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि पहले भी इस पर सवाल उठ चुके हैं और सरकार अगर अपने आप को संप्रभु समझती है तो व्यापक जनहित में अमेरिका से किया गया परमाणु समझौता भी रद्द कर देना चाहिए। लोग़ों को यह समझ लेना चाहिए कि परमाणु उर्जा अन्य स्रोतों से मिलने वाली उर्जा से काफ़ी महंगी होती है और ख़तरनाक कितनी होती है, इसे लोग़ों ने देख ही लिया है।

- मनोज कुमार झा

ट्रैफ़िक पुलिस को ट्रैक्टर दिखाई दे ही गये

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर की दिनोंदिन बिगड़ती ट्रैफ़िक समस्या को बद से बदतर बनाते ट्रैक्टर ट्रालों की ओर ट्रैफ़िक पुलिस का ध्यान आकृष्ट करने के लिए 'मज़दूर मोर्चा' पिछले काफ़ी समय से प्रयासरत रहा है। कृषि कार्यों के लिये बने ट्रैक्टरों का शहर की सड़कों अथवा राजमार्गों पर चलना, खास कर व्यावसायिक रूप से चलना ग़ैरकानूनी है। इसके बावजूद ये ट्रैक्टर न केवल चलते हैं, बल्कि बहुत ही ख़तरनाक और ग़ैरज़िम्मेदाराना तरीके से चलते हैं। 'मज़दूर मोर्चा' द्वारा किये गये एक सर्वे में पाया गया था कि शहर में नियमित रूप से चलने वाले 1200 ट्रैक्टर पुलिस वालों को एक हज़ार रुपया मासिक देते हैं तथा ग्रामीण इलाकों से ईंट, रेत आदि ले कर आने वाले हज़ारों ट्रैक्टर पुलिस नाकों पर बाकायदा 'एन्ट्री फ़ीस' अदा करते हैं। उच्चाधिकारियों से इस बाबत बात करने पर उनका कुतर्क यह होता था कि ट्रैक्टर ग़रीब किसानों का वाहन है, इसलिए इसे सड़कों पर चलने से रोकने का मतलब होगा उन्हें आंदोलन करने के लिए आमंत्रित करना। लेकिन अब 23 मार्च को यकायक ट्रैफ़िक पुलिस को यह बात कैसे समझ में आ गयी कि ये ट्रैक्टर किसानों के न होकर व्यवसायियों के हैं और ट्रैफ़िक व्यवस्था को सुधारने के लिए इन पर अंकुश लगाना आवश्यक है। सुनने में आ रहा है कि एक विशेष पखवाड़ा मना कर इन ट्रैक्टरों को सड़कों से हटाया जायेगा या उन्हें व्यवसायिक रूप से पंजीकृत हो कर ही सड़कों पर उतरने दिया जायेगा। पंजीकृत होने वाले ट्रैक्टरों को बाकायदा सड़क पर चलने लायक शर्तों का पालन भी करना होगा। लगता है कि इस तरह के पखवाड़े शायद मनाये ही इसलिए जाते हैं कि अवैध वाहन चालकों को उनकी अवैधता का समय-समय पर ज्ञान कराया जाये ताकि मंथली वसूलने में कोई दिक्कत न आये, वरना जो वाहन अवैध है, वह कभी भी सड़क पर आये ही क्यों? इसके लिए किसी तरह के पखवाड़ों की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

महेन्द्र नैन सिंह को हरियाणा साहित्य अकादमी का पुरस्कार

फ़रीदाबाद (म.मो.) मज़दूर लेखक महेन्द्र सिंह नैन को हरियाणा साहित्य अकादमी ने उनके उपन्यास 'आर्यावर्त का सम्राट' के लिए सम्मानित किया है। इनके साथ ही शहर की लेखिका डॉ. अंजु जैमिनी को भी उनके निबंध 'मोर्चे पर स्त्री' के लिए पुरस्कृत किया गया। 29 मार्च को चंडीगढ़ में आयोजित समारोह में श्रम एवं रोजगार मंत्री पं. शिवचरण लाल शर्मा ने वर्ष 2008-09 के लिए नैन को प्रशस्ति-पत्र व नकद पुरस्कार दे कर सम्मानित किया। कवयित्री जैमिनी को वर्ष 2009-10 के लिए सम्मानित किया गया। महेन्द्र सिंह नैन इस शहर के सारन गांव के निवासी हैं। ये कवि, कथाकार और शोधकर्मी हैं। इनके कई कहानी संग्रह, उपन्यास, कविता-संग्रह और शोध पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने हायर सेकेंडरी तक शिक्षा पाई है।

आज जब साहित्य के क्षेत्र में मध्य वर्ग काबिज़ है, इन्होंने दिखा दिया है कि मज़दूर वर्ग का भी एक व्यक्ति लेखन के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर सकता है। महेन्द्र सिंह नैन का पूरा व्यक्तित्व एक सच्चे लेखक का है। लेखन इनके लिए कोई शौक अथवा मजबूरी नहीं है। लेखन इनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। लेखन के लिए इन्होंने कड़ा जीवन-संघर्ष किया है। आजीविका के लिए इन्होंने कई फ़ैक्ट्रियों में मज़दूरी की, रेहड़ी चलाई और इसके अलावा भी कई तरह के काम किये। फ़िलहाल ये एस्कार्ट कंपनी में कैजुअल टूलरूम वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। 'मज़दूर मोर्चा' इन्हें हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किये जाने पर बधाई देता है और यह कामना करता है कि लेखन के क्षेत्र में इनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा और वे एक से एक नयी कृतियां समाज को देंगे। नैन का मोबाइल नंबर : 9350652493